विदेश में हिंदी शिक्षण के लिए मानक पाठ्यक्रम तैयार करने का दायित्व हिंदी विश्वविद्यालय को

यूएन में हिंदी को स्थान दिलाने का संकल्प

वर्धा दि. 5 अक्तूबर 2012 : विदेश में हिंदी शिक्षण के लिए मानक पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। यह संकल्प 24 सितंबर को नौवें विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह में लिया गया। इसमें दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। दक्षिण अफ्रीका के सैंडटन शहर में नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन 24 सितंबर को समाप्त हो गया। आयोजन समिति के सदस्य एवं संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष सत्यव्रत चतुर्वेदी ने सम्मेलन में हिंदी के उत्थान हेतु लिए गए संकल्पों की जानकारी दी। इसमें हिंदी को यूएन की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने का संकल्प लिया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) में हिंदी को सातवीं आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए अब समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस आशय के प्रस्ताव 1975 में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन और उसके बाद भी पारित किए जा चुके हैं। लेकिन, अब तक इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी है। नौवें सम्मेलन की अध्यक्ष भारत की विदेश राज्य मंत्री प्रनीत कौर ने भी इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। सम्मेलन में यह भी तय किया गया है कि अब दो विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन के बीच अधिकतम तीन वर्ष का ही अंतराल रखा जाएगा और सम्मेलन में हिंदी के विद्वानों को दिया जाने वाला सम्मान विश्व हिंदी सम्मान के नाम से जाना जाएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी में देवनागरी लिपि के प्रयोग पर पर्याप्त सॉफ्टवेयर तैयार किए जाएं। मॉरीशस में स्थापित विश्व हिंदी सचिवालय को विभिन्न देशों के हिंदी शिक्षण से संबद्ध विश्वविद्यालयों, पाठशालाओं और शैक्षणिक संस्थाओं का डाटाबेस तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह सचिवालय दुनिया भर के हिंदी विद्वानों, लेखकों और हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित लोगों का डाटाबेस भी तैयार करेगा। नौवें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी सेवा के लिए 41 विद्वानों को सम्मानित किया गया। इनमें 22 विदेशी मूल के हैं।

बी एस मिरगे
जनसंपर्क अधिकारी